ALL INDIA CONGRESS COMMITTEE
24, AKBAR ROAD, NEW DELHI
COMMUNICATION DEPARTMENT

Highlights of Press Briefing **07 December, 2020**

Shri Sunil Jakhar, President of Punjab Pradesh Congress Committee, addressed the media at AICC Hdqrs, today.

श्री सुनील जाखड़ ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं जब आपसे मुखातिब हो रहा हूं, जो आज टेक्नोलॉजी मीडियम के जरिए आप सब जुड़े हुए हैं, वहीं मैं आपके माध्यम से हमारे जो लाखों किसान, जैसे अभी झा साहब ने कहा कि दिल्ली की ड्योढ़ी पर बैठे हैं, मैं समझता हूं कि किसान आज दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं। बॉर्डर पर किसान बैठा है, दिल्ली के बॉर्डर पर और हिंदुस्तान एवं चीन के बॉर्डर पर किसान का बेटा बैठा है। ये अतिश्योक्ति नहीं होगी कि बॉर्डर के ऊपर, देश के बॉर्डर के ऊपर चाहे वो पाकिस्तान के साथ, चाहे चीन के साथ, आज जो हमारे बहादुर सैनिक तैनात हैं, उनमें बहुत बड़ा हिस्सा ग्रामीण पृष्ठभूमि से, किसानी से जुड़े हुए उन नौजवानों का है, जो देश की रक्षा के लिए कभी भी जान कुर्बान करने से नहीं झिझकते। तो मैं समझता हूं कि आज इस देश का भी दायित्व बनता है कि उन जवानों से जुड़े हुए उनके परिवार जब आज दिल्ली के बॉर्डर पर आकर बैठने, अपने देश की राजधानी के बॉर्डर के ऊपर आकर जैसे बैठे हैं और जिस तरह से इन किसानों को दिल्ली में आने से रोका गया, जिस तरह से सड़कें खोदी गई, जिस तरह से आंसू गैस इस्तेमाल की गई, जिस तरह से इस ठंड़ के अंदर गंदे पानी की बौछारें इस कोरोना के माहौल में जब उन पर बरसात की गई, तो यूं लगता था कि जैसे किसी आक्रामक देश की फौजें दिल्ली के ऊपर चढ़ाई कर रही हों।

ये हालात क्यों पैदा हुए- मैं समझता हूं कि आज एक अहम मुकाम है जब ये देश को फैसला करना होगा कि इस परिस्थिति का जिम्मेदार कौन है? Responsibility will have to be fixed, किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा नहीं, मैं समझता हूं आम नागरिक देश का, चाहे वो शहर के अंदर बैठा है, चाहे वो गांव के अंदर बैठा है, चाहे वो किसान है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो कर्मचारी है, सबको ये फैसला करना होगा कि जिसे अन्नदाता कहते हैं, उसे आज इस कड़कड़ाती ठंड के अंदर क्यों आज बाहर बैठना पड़ा है, अपनी फसलों को छोड़कर आज दिल्ली के बॉर्डर पर गुहार लगाई जा रही है।

आज जब किसान ने देशबंद का आह्वान किया है, तो मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये आह्वान करता हूं हमारे सभी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को और सभी लाइक माइंडेड पीपुल को कि वो बढ़-चढ़ कर

इस बंद में सहयोग दें ताकि सत्ता के अहंकार में बहरी हुई सरकार, आंखें मूंदी हुई सरकार की आंखे खोली जा सकें और इनके कान खोले जा सकें।

आज जो हालात बने हुए हैं, आज जिस तरह से किसान बॉर्डर पर बैठा है, मैं ये बात देश के प्रधानमंत्री के ध्यान में लेकर आना चाहता हूं, जो मुख्य मुद्दा आज की प्रेस वार्ता का आपके माध्यम से शेयर करना चाहता हूं कि ये वो किसान हैं, जिनके बच्चे बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं। देश की नेशनल सिक्योरिटी का अभिन्न अंग है हमारा खाद्यान सिक्योरिटी, Our food security is integral part of our national security. Neither the national security can be outsourced, nor the food security can be outsourced? ना तो भाड़े के या ठेके के सैनिक देश की सुरक्षा कर सकते हैं और ना ही भाड़े के किसान देश का पेट भर सकते हैं। अगर देश के खाद्यान भंडार, देश में खाद्यान सुरक्षा होगी तो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा भी मजबूत होगी, क्योंकि वो दिन याद करिए जब PL 470 के तहत लाखों टन करीबन 10 मिलियन टन अनाज अमेरिका से मंगवाया जाता था, तब हमारी फॉरेन पॉलिसी उनकी गुलाम थी और देश की सॉवरेनिटी, प्रभुसत्ता खाद्यान सुरक्षा के ऊपर निर्भर करती है। तो मैं समझता हूं कि कोई भी देश का नागरिक ये नहीं स्वीकार करेगा कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा किसी साहूकारों के पास ठेके पर दे दी जाए और वो भाड़े के सैनिक प्रोवाइड करवाएं, चीन से, पाकिस्तान से दो-दो हाथ करने के लिए और ना ही देश का किसान ठेके पर साहूकारों के हाथ से चल सकता है। किसान से आज जिस किस्म का व्यवहार किया जा रहा है और जिस तरह से चर्चा हुई कि आज किसान की समस्या का हल ना करके, देश की सत्ता में बैठे जो लोग हैं, देश के माननीय प्रधानमंत्री नए पार्लियामेंट, नए संसद भवन की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मैं उनसे एक बात कहना चाहूंगा कि इसके ऊपर पैसा व्यर्थ करने की शायद जरुरत नहीं है, क्योंकि बिल्डिंग से संसद नहीं चला करती, संसद भावनाओं से और कॉन्सटिट्यूशन के ऊपर आधारित है। वो हमारी जो लोकतंत्र की प्रणाली है, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर साहब ने हमें हमारा संविधान दिया है, उसकी मूल भावना से हटकर, जब आपने विज्ञान भवन को एक डीम्ड पार्लियामेंट का दर्जा दे दिया है, तो ऐसे हालात के अंदर मैं नहीं समझता कि हजारों-करोड़ रुपए लगाकर नया संसद भवन बनाने की जरुरत आज के दिन है। जब देश के विपक्ष, जब संसद चल भी रही थी, तब भी सांसद इस बात के लिए मजबूर थे कि महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने उन्हें रात भर धरना देना पड़ा और जो हमारे माननीय सभापति हैं, स्पीकर महोदय सुबह जब चाय और नाश्ता लेकर आए तो उन्होंने कहा था कि मेरी भावना आहत हुई है। मैं उनकी भावना की कद्र करता हूं, पर मैं समझता हूं देश की और किसान की भावना जिस तरह से आहत हुई है, उसका आज बीजेपी और बीजेपी के लीडर साहेबान हैं, वो संज्ञान नहीं ले रहे हैं।

आज उनसे जो बातचीत विज्ञान भवन में हो रही है, मैं समझता हूं ये बातचीत ऑर्डिनेंस बनाने से पहले या ऑर्डिनेंस लागू होने के बाद भी जब उन्हें कानून का रुप दिया गया और ये सदन के अंदर मूव किया गया तो उन बातों के ऊपर चर्चा वहाँ पर होनी चाहिए थी। आज किसान बंधुओं को, मैं

समझता हूं कि जो चर्चा आज टीकरी बॉर्डर के ऊपर हो रही हैं, वो वार्तालाप संसद में होनी चाहिए थी और मैं समझता हूं कि हमारी संसद की जो बिल्डिंग है, बडी भव्य बिल्डिंग है, उसमें भी ये चर्चा हो सकती थी और ये चर्चा टेंट में भी हो सकती है। हजारों करोड़ रुपए आज देश को, जब किसान भूखा मर रहा है, तो किसी को इसका औचित्य समझ में नहीं आ रहा है। मेरी विनती आज के माहौल में सिर्फ इतनी ही है कि अमेरिका का अनुसरण ना करें और अमेरिका में भी लोबिंग की जो प्रथा है, वो चंद सैनिटर तक है कि आप कोई भी देश, कोई भी कंपनी अपने लोबिस्ट के तौर पर उन्हें एंगेज कर सकती है, परंतु ये बातें शायद अमेरिका में भी स्वीकार्य ना हो कि देश की सरकार जो है, साहूकारों के लिए लोबिस्ट का काम कर रही है। Corporatizing the agriculture is neither acceptable nor can be in any way expected by the people of India. ना तो आउट सोर्सिंग हमारी खेती की होने देंगे, ना ही हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की होने देंगे और इस बात का संज्ञान देश के प्रधानमंत्री लें और इस बातचीत का फौरी तौर से निपटारा करें। जो काले कानून हैं, इनको वापस लिया जाए, क्योंकि इन कानूनों के अंदर सिर्फ गलती मात्र नहीं है कि जो 29 प्वाइंट किसान साथियों ने इस सरकार को समझाने का प्रयास किया। इसकी मूल भावना जो है, the basic objective and the intent, वही आज शक के दायरे में खड़ी है, क्योंकि सिर्फ दाल में काला नहीं है, सारी दाल ही काली है। इसे नाम बदलकर जिस अंमेंडमेंट पर राजी हो रहे हैं, मैं समझता हूं उसके साथ अपने इरादे भी अमेंड करने पडेंगे।

आज जिन बातों का जिक्र नहीं हो रहा है, जिन बातों को लेकर देश के अंदर भ्रमित किया जा रहा है। मैं समझता हूं देश के माननीय प्रधानमंत्री पूरी तरह से अवगत नहीं है। क्योंकि उन्होंने अपनी जो लास्ट मन की बात की और उन्होंने जिस महाराष्ट्र के किसान जितेन्द्र का जिक्र किया, मक्का किसान की बात की कि उसे इन नए कानूनों के जरिए उसकी कीमत मिली, आज वही किसान इस आंदोलन में आकर भागीदार बना हुआ है और उसी के शब्दों के मुताबिक उसे एमएसपी नहीं मिली। जो एमएसपी 1,850 रुपए के करीब मिलनी चाहिए थी, 1,200 रुपए में उसने अपना मक्का बेचा और 2 लाख रुपए का उस किसान को नुकसान हुआ।

तो मैं समझता हूं इस अहंकार को छोड़कर आज किसानों के बीच वार्तालाप सिरे पर इसलिए नहीं चढ़ रही कि इसके बीच में बीजेपी का अहंकार आया हुआ है। अगर किसानों की बात नहीं सुनना चाहते बीजेपी के शीर्ष नेता, तो मैं समझता हूं कि अपने स्वदेशी जागरण मंच के उनके साथियों की बात सुन लें, अपने किसान संघ की बात सुन लें, परंतु इस मसले का जल्दी से जल्दी निपटारा हो, क्योंकि बार-बार जिस तरह से किसानों को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं समझता हूं किसानों के धैर्य की परीक्षा ली जा रही है। आज किसानों के धैर्य की परीक्षा का समय नहीं हैं, आज देश की, इनकी समझदारी का, मैं समझता हूं उनकी capability to carry the nation along, आज इम्तेहान इस सरकार का है कि क्या वो सबको साथ में लेकर चल पाएंगे या किसानों को सबसे पहले हुलीगन कहा गया, फिर आतंकवादी कहा गया और तरह –तरह के नाम देकर

उनको बांटने का प्रयास किया गया, जो बहुत ही निंदनीय है और मैं समझता हूं कि इस सरकार को यह शोभा नहीं देता। और जिस तरह से आज गोरे अंग्रेज चले गए परंतु काले अंग्रेज आज भी उस भावना को लिए घूम रहे हैं। डिवाइड एंड रुल की जो पॉलिसी है, जो नया शगुफ़ा आज छोड़ा गया है, जिसके तहत बीजेपी के कुछ सीनियर लीडर और मंत्री ये कहते हुए नजर आए हैं अपने हरियाणा के उन किसानों को जिनको कल तक माननीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब कह रहे थे कि हरियाणा का कोई भी किसान नहीं है।

देश का किसान आज किसी भी राजनैतिक दायरे से ऊपर उठकर जैसे प्रणव झा साहब ने कह दिया कि ये लहर जो थी, ये लहर बिल्कुल पंजाब से चली और मुझे इस बात का फ़ख्र है कि पंजाब ने जहाँ पर हरित क्रांति में पायनियर रोल निभाया, एक लीडर का रोल निभाया। आज भी देश में किसानी के कॉर्पोरेइटाइजेशन को लेकर जो गुस्सा जताया गया है देश को, तो वह पंजाब का किसान था। हमें गर्व है और कांग्रेस को उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का। परंतु ये जो आज आंदोलन है, ये आंदोलन नहीं क्रांति है और ये क्रांति किसानों की, आम जन की क्रांति है, जो किसानी से आगे बढ़कर, मैं चंद लाइनें यहाँ पर हमारे पंजाबी के बहुत बड़े कवि हैं. उनकी आपसे शेयर करना चाहूंगा - एह बात निरी एन्नी ही नहीं, एह मसला सिर्फ किसान दा नहीं, एह पिंड दे वसण दा है, जिन तोखला उज्जड़ जांदा है।

आज गांव के उजडने का मुद्दा है, आज अकेला किसानी का मुद्दा नही हैं। जिन आढ़तियों को ये लोग अपना व्यापारी भाई बताया करते थे, बीजेपी वाले, वो आढती भी, वो मजदूर भी, वो शहर के लोग भी और सभी किसान आज उस गांव में, उस ग्रामीण जीवन शैली को उजडने की जो नीति को लेकर जो ये सरकार आई है, उसके खिलाफ आज सारा देश जागृत हुआ खड़ा है और मेरी यही विनती होगी माननीय प्रधानमंत्री से कि इस मुद्दे को फौरी तौर से निपटाया जाए। इन काले कानूनों को वापस लिया जाए और नए सिरे से पार्लियामेंट के अंदर बैठकर, उसी पुरानी बिल्डिंग में परंतु नई भावना के साथ बीजेपी एक लोकतांत्रिक भावना की कद्र करते हुए खुले मन से, बातचीत दो तरफा हुआ करती है, क्योंकि अब से 5 वें दौर से पहले जितनी भी वार्तालाप किसानों से हुई, वो एक तरफा बातचीत हुई। वो मन की बात किस सरकार की बताई गई, किसानों के मन की बात नहीं सुनी गई। किसानों के मन की बात सुनें बिना इस मुद्दे का हल नहीं किया जा सकता।

एक बार फिर से मैं दोहराउंगा और मैं धन्यवादी हूं उन सभी लाइक मांइडेड पार्टी का, देशभर में जो कल के 8 तारीख के पूरे भारत बंद में पूरा सहयोग कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को आह्वान करुंगा कि डट कर कल के इस भारत बंद में किसान संगठनों का सहयोग दें और पंजाब में कांग्रेस पार्टी हर जिला स्तर पर किसानों के हक में धरना प्रदर्शन करेगी।

जय हिंद।

एक प्रश्न पर कि कल जो भारत बंद हो रहा है, उससे आम जन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्या कहेंगे? श्री सुनील जाखड़ ने कहा कि मैंने अपनी बातचीत की यहीं से शुरुआत की थी कि जो हालात बने हैं, जिसका बिल्कुल आपका मानना सही है कि कल कुछ लोगों को इससे परेशानी होगी, परंतु इस परेशानी का दायित्व इस मोदी साहब की सरकार के दरवाजे पर फेयरली एंड स्क्वेयरली है, उनके यहाँ लाइ करता है। जो बातचीत, जो आज ये कर रहे हैं, ये बातचीत अगर इन्होंने जब ये ऑर्डिनेंस अध्यादेश लेकर आए थे 5 जून को, उससे पहले बातचीत कर ली जाती और जिन अमेंडमेंट्स को लेकर जिनकी बात आज ये मान रहे हैं कि अमेंडमेंट होनी जरुरी है और अपनी गलती को मानते हैं, अगर ये पहले कर ली जाती तो देश को ये दिन नहीं देखने पड़ते। आज जो लोग असुविधा की बात करते हैं, मैं उनको ये भी कहना चाहूंगा कि आज अन्नदाता जो है आज इस कड़कती सर्दी के अंदर वहाँ बैठा है, बुजुर्ग बैठे हैं, माताएं-बहनें बैठी हैं और अपने बच्चों को लेकर बैठे हैं, एक बार उनकी तरफ नज़र जरुर मारकर देख लें। आज मैं समझता हूं उस असुविधा का देश के आकाओं को, उनकी अंतरआत्मा को जगाने का रत्ती मात्र भी उसमें सहयोग हो सकता है तो मैं सबसे अपील करुंगा कि अपनी इस परेशानी को एक तरफ रखकर किसानों की इस जायज़ मांग के अंदर उनका साथ दें।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री जाखड़ ने कहा कि सरकार का जो अड़ियल रवैया है, इस सरकार की क्रेडिब्लीटी, This is not a lack of trust. There is not a trust deficit as they said; there is a total lack of credibility. इस इस सरकार की मंशा पर खोट होने का जो आरोप लग रहा है, वो बेबुनियाद नहीं है। ये वही सरकार है, जब नोटबंदी लेकर आए थे, तो कालाधन खत्म करने की बात की थी। पुरानी बात ना करें, मैं ताजी बात करना चाहूंगा, लॉकडाउन होने से कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि रेलवे की जो प्राईवेटाइजेशन की होने की बात हो रही है, वो बिल्कुल बेबुनियाद है, पर आज वही रेलवे जो है प्राईवेटाइज कर दी गई। ये वही सरकार है जिन्होंने कहा था कि मुझे 21 दिन का समय दीजिए, कोरोना को खत्म कर दूंगा। आज सरकार की क्रेडिबिल्टी बिल्कुल निल है, जिसके चलते आज कोई भी संगठन, किसान छोड़ कोई भी संगठन सरकार की किसी भी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं है। ये आंदोलन आज नहीं चल रहा है, ये आंदोलन आज से नहीं चल रहा है, ना मुझे उम्मीद है कि 9 तारीख को खत्म होगा जिस किस्म का अडियल रवैया, आज उनके जिस किस्म के आरएसएस के उनके साथियों के बयान आए हैं कि जो कुछ किसानों को मिल रहा है वो स्वीकार कर लें, इससे फालतू जायज कुछ नहीं है, तो ना ही खत्म होगा। तो मैं समझता हूं सारी की सारी जिम्मेदारी इस सरकार पर है और इस बात का इनको भुगतान करना पड़ेगा।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री जाखड़ ने कहा कि मैं समझता हूं कि इसमें चंद बिंदुओं की बात नहीं हैं, 29 खामियों की बात नहीं है, जो कांग्रेस पार्टी कह रह है। the very objective जिस मंशा से ये कानून लेकर आए हैं, ये व्यापारीकरण करने के लिए किया गया है, कॉर्पोरेटाइजेशन करने के लिए

किया गया है, हम उसके खिलाफ हैं। ये राहुल जी और कांग्रेस पार्टी बार-बार कह रही है कि हर एक व्यवस्था के अंदर इंप्रूवमेंट का उसमें सुधार लाने की गुंजाइश होती है। There is a lot improvement which can be done. लेकिन जिस मंशा से ये लेकर आया गया है, किसानी में से मलाई खाने के लिए इन साहूकारों को आगे लाया जा रहा है, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, चैरी पिकिंग। चैरी पिकिंग आज कुछ जो इंटलैक्चुअल क्लास है, जो आज तक इनकी हामी भर रहे थे, अब वो भी बात करने लगे कि this corporatization or these laws will enable these corporates to cherry pick and what is very important is that they will be privatizing the profit and nationalizing the losses. जो बोझ होगा, जो आज नुकसान है, वो सारे राष्ट्र के माथे पर मंढ़ा जाएगा और किसान के माथे पर मंढ़ा जाएगा और जहाँ कहीं भी दो पैसे बनते हैं, 25 लाख करोड़ का जो धंधा है, वो साहूकारों को थाली में रखकर परोसने का जो प्रयास किया जा रहा है, हम उसके ख़िलाफ हैं। पार्लियामेंट के अंदर ये मसले डिस्कस किए जाएं कि कौन से सुधारों की जरुरत है।

आप कह रहे हो क्योंकि मैं किसान की भाषा में बात करूँगा कि किसान कह रहा है कि आप मेरी आँख फोड़ रहे हो और बीजेपी-माननीय प्रधानमंत्री कह रहे हैं हम आपकी आँख में काजल डाल रहे हैं। तो ऐसा काजल किसान को मंजूर नहीं है, तो नए सिरे से सारे ऐसे कानून ख़ारिज करके, किसानों से राय करके उसके बाद में इस मसले के ऊपर चर्चा होकर आगे कदम उठाया जाए।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री जाखड़ ने कहा कि कांग्रेस का आज मसला नहीं है। कांग्रेस ने अपनी बात रख दी है। आज मसला किसानों का है और किसानों ने अपनी बात भी रख दी है, और उन्होंने कल- परसों जो स्टैंड लिया, हाँ या न। बातचीत बहुत हो गई, बातचीत नहीं, मन की बात सुनी है उन्होंने। उनकी बात सुनने का समय आ गया है। तो मैं समझता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री संज्ञान लें।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री जाखड़ ने कहा कि मैं समझता हूँ कि आज कांग्रेस के पंजाब के हमारे सांसद जो हैं जंतर-मंतर में इसी बात को लेकर बैठे हैं कि फौरी तौर पर एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई जाए लोकसभा की, सांसदों की मीटिंग बुलाई जाए और उसमें इन बिलों को निरस्त किया जाए और उसके बाद नए सिरे से चर्चा चालू हो। किसानों के जो संगठन हैं, जिनसे आज विज्ञान भवन में बात हो रही है, उनसे लोकसभा के अंदर बातचीत हो, राज्यसभा में इसके ऊपर चर्चा हो और उसके बाद में अगला कदम लिया जाए। विश्वसनियता आप देख लीजिए कि नवम्बर की बात है, जब माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होगी। मार्च के अंदर माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि 21 दिन के अंदर कोरोना खत्म हो जाएगा, किस तरह से यकीन कर लें। मेरी भावना है क्योंकि वो बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं और मैं भी चाहता हूँ कि मैं प्रधानमंत्री जी की बात पर भरोसा करूँ, लेकिन उनका इतिहास पलटकर देखते हैं तो उसमें कहीं भी यकीन के लिए जगह नहीं है।

Sd/-
(Dr. Vineet Punia)
Secretary
Communication Deptt,
AICC